Shodhbodhalaya: An International Peer reviewed
Multidisciplinary Journal
Volume 4 | Issue 1 | ISSN: 2584-1807 | (https://shodhbodh.com/)

रीवा जिले के औद्योगिक विकास में राज्य शासन की विविध योजनाओं का योगदान- मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के विशेष संदर्भ में

Contribution of Various State Government Schemes in the Industrial Development of Rewa District:With Special Reference to Mukhyamantri Swarozgar Yojana

शोध–निर्देशक

डॉ. अंकुल पाण्डेय

सहा. प्राध्यापक, वाणिज्य विभाग

शासकीय ठाकुर रणमत सिंह स्वशासी महाविद्यालय

रीवा (म.प्र.)

शोधार्थी

विश्वदीपक चतुर्वेदी

वाणिज्य विभाग

1. सारांश (Abstract)

प्रस्तुत शोध पत्र मध्यप्रदेश के रीवा जिले में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के माध्यम से हो रहे औद्योगिक विकास की विवेचना करता है। राज्य शासन द्वारा संचालित यह योजना स्थानीय युवाओं, महिलाओं एवं अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के लोगों को स्वरोजगार की दिशा में प्रशिक्षण, ऋण सहायता एवं सब्सिडी प्रदान कर उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का प्रयास करती है। इस अध्ययन में वर्ष 2018-19 से 2022-23 तक के द्वितीयक आंकड़ों का विश्लेषण किया गया है जिसमें लाभार्थियों की संख्या, ऋण वितरण, क्षेत्रवार एवं सामाजिक वर्गवार वितरण, ऋण वापसी की स्थिति तथा रोजगार सृजन के पहलुओं को शामिल किया गया है। अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि योजना रीवा जिले के औद्योगिक परिदृश्य को सकारात्मक रूप से प्रभावित कर रही है, परंतु कार्यान्वयन में कुछ संरचनात्मक चुनौतियाँ भी विद्यमान हैं जिनके निराकरण हेतु प्रभावी नीतिगत हस्तक्षेप की आवश्यकता है।

2. मुख्य शब्द (Keywords)

मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, रीवा जिला, औद्योगिक विकास, स्वरोजगार, ऋण वितरण, राज्य शासन की योजनाएँ, रोजगार सृजन, उद्यमिता, मध्यप्रदेश, सामाजिक-आर्थिक विकास, सूक्ष्म एवं लघु उद्योग।

3. प्रस्तावना (Introduction)

भारत में स्वतंत्रता के पश्चात् से ही ग्रामीण एवं अर्ध-शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी एक प्रमुख सामाजिक-आर्थिक समस्या रही है। मध्यप्रदेश के बुंदेलखंड एवं बघेलखंड संभाग के जिले, विशेषतः रीवा, ऐतिहासिक रूप से आर्थिक पिछड़ेपन, रोजगार के अभाव एवं पलायन की समस्याओं से ग्रसित रहे हैं। इस संदर्भ में मध्यप्रदेश शासन द्वारा मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का प्रारंभ एक महत्वपूर्ण नीतिगत हस्तक्षेप है।

रीवा जिला मध्यप्रदेश के उत्तर-पूर्वी भाग में स्थित है तथा यह बघेलखंड संभाग का प्रमुख जिला है। जिले की अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि पर आधारित है, परंतु विगत एक दशक में रीवा में सफेद सीमेंट उद्योग, पाइराइट्स, हाइड्रो पावर प्लांट (बाणसागर परियोजना) तथा सोलर ऊर्जा क्षेत्र में उल्लेखनीय निवेश हुआ है। इन पृष्ठभूमि में स्थानीय स्तर पर सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के विकास के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है।

मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना मध्यप्रदेश शासन की एक प्रमुख योजना है जिसे सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग (MSME) द्वारा क्रियान्वित किया जाता है। इस योजना के अंतर्गत 18 से 45 वर्ष आयु वर्ग के बेरोजगार युवाओं, महिलाओं एवं अनुसूचित वर्गों को ₹50,000 से ₹10 लाख तक की ऋण सहायता, प्रशिक्षण एवं सब्सिडी प्रदान की जाती है। योजना का मुख्य उद्देश्य न केवल स्वरोजगार को बढ़ावा देना है, अपितु जिले में औद्योगिक संस्कृति के विकास को भी प्रोत्साहित करना है।

4. शोध पत्र के उद्देश्य (Objectives)

प्रस्तुत शोध पत्र के निम्नलिखित उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं:

1. रीवा जिले में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत वर्ष 2018-19 से 2022-23 तक के लाभार्थियों की संख्या एवं ऋण वितरण की प्रवृत्ति का विश्लेषण करना।

2. योजना के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों (विनिर्माण, खाद्य प्रसंस्करण, सेवा, व्यापार, कृषि आधारित) में लाभार्थियों के वितरण का अध्ययन करना।
3. सामाजिक वर्गवार (SC/ST/OBC/सामान्य/अल्पसंख्यक) एवं लिंगवार (महिला/पुरुष) लाभार्थियों के वितरण की स्थिति का परीक्षण करना।
4. ऋण वापसी की स्थिति एवं अनर्जक आस्तियों (NPA) की प्रवृत्ति का आकलन करना।
5. विकासखंडवार लाभार्थी वितरण की असमानताओं का अध्ययन कर विकास के भौगोलिक असंतुलन को उजागर करना।
6. योजना की उपलब्धियों एवं कार्यान्वयन में आने वाली चुनौतियों की पहचान कर सुधारात्मक सुझाव प्रस्तुत करना।

5. शोध पत्र का महत्व (Significance)

प्रस्तुत शोध पत्र विभिन्न दृष्टिकोणों से महत्त्वपूर्ण है:

शैक्षणिक महत्व: यह शोध पत्र विकास अर्थशास्त्र, लोक प्रशासन एवं समाजशास्त्र के क्षेत्र में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के समाजशास्त्रीय एवं आर्थिक प्रभावों का एक प्रामाणिक दस्तावेज प्रस्तुत करता है। रीवा जैसे पिछड़े जिले में इस योजना के प्रभावों पर केंद्रित अध्ययन अत्यंत सीमित हैं, इस दृष्टि से यह शोध पत्र उस शोध-अंतराल को पाटने में सहायक है।

नीतिगत महत्व: इस शोध पत्र में प्रस्तुत विश्लेषण एवं सुझाव जिला प्रशासन, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के नोडल अधिकारियों तथा राज्य शासन के नीति-निर्माताओं के लिए उपयोगी संदर्भ-सामग्री प्रस्तुत करते हैं। कार्यान्वयन की कमियों को उजागर कर यह अध्ययन योजना के प्रभावी क्रियान्वयन में सहायक हो सकता है।

सामाजिक महत्व: यह अध्ययन योजना के सामाजिक न्याय के पहलू को उजागर करता है, विशेषतः SC/ST वर्ग एवं महिला लाभार्थियों तक योजना की पहुँच की स्थिति के संदर्भ में। यह जानकारी समाज में समावेशी विकास को बढ़ावा देने में महत्त्वपूर्ण है।

क्षेत्रीय विकास: रीवा जिले की आर्थिक स्थिति, भौगोलिक विशेषताओं एवं औद्योगिक संभावनाओं के परिप्रेक्ष्य में यह अध्ययन क्षेत्रीय विकास की रणनीति निर्धारण में सहायक है।

6. साहित्य समीक्षा (Literature Review)

शर्मा (2018) ने मध्यप्रदेश में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के प्रभावों का व्यापक अध्ययन किया और पाया कि योजना ने शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक प्रभावशाली परिणाम दिए हैं। मिश्रा एवं पांडेय (2019) ने बघेलखंड क्षेत्र में स्वरोजगार योजनाओं का तुलनात्मक अध्ययन कर यह निष्कर्ष निकाला कि प्रशिक्षण की गुणवत्ता एवं बाजार संपर्क स्वरोजगार की सफलता के प्रमुख निर्धारक हैं।

यादव (2020) ने मध्यप्रदेश के विंध्य क्षेत्र में सरकारी योजनाओं के औद्योगिक प्रभाव का विश्लेषण करते हुए पाया कि ऋण की सुगम उपलब्धता एवं समय पर वितरण उद्यम की सफलता में निर्णायक भूमिका निभाता है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्माल बिजनेस डेवलपमेंट (NIESBUD, 2021) की रिपोर्ट में स्वरोजगार योजनाओं में महिला भागीदारी को बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया गया है। तिवारी एवं सिंह (2022) ने रीवा जिले की आर्थिक संरचना का अध्ययन करते हुए निष्कर्ष निकाला कि जिले में उद्यमिता की संभावनाएँ प्रचुर हैं, किंतु जागरूकता एवं कौशल विकास की कमी एक बड़ी बाधा है।

7. शोध पद्धति (Research Methodology)

यह अध्ययन मुख्यतः द्वितीयक आंकड़ों पर आधारित है। आंकड़ों के स्रोतों में जिला उद्योग एवं व्यापार केंद्र (DIC), रीवा; मध्यप्रदेश MSME विभाग की वार्षिक रिपोर्ट; राज्य सरकार के पोर्टल पर उपलब्ध योजना रिपोर्ट; जिला सांख्यिकीय पत्रिका, रीवा; तथा राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के प्रासंगिक आँकड़े सम्मिलित हैं।

आंकड़ों के विश्लेषण हेतु वर्णनात्मक सांख्यिकी, प्रवृत्ति विश्लेषण, प्रतिशत विश्लेषण एवं सारणीबद्ध प्रस्तुतीकरण विधियों का उपयोग किया गया है। अध्ययन की समयावधि 2018-19 से 2022-23 (पाँच वर्ष) है।

8. आंकड़ों की सारणी एवं विश्लेषण (Data Tables and Analysis)

सारणी 1:

मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना — रीवा जिले में वार्षिक प्रगति

क्र.	वर्ष	आवेदन प्राप्त	स्वीकृत आवेदन	लाभार्थी संख्या	वितरित ऋण (लाख रु.)	प्रशिक्षित लाभार्थी
1	2018-19	1,842	1,124	1,098	548.60	312
2	2019-20	2,318	1,487	1,432	716.40	428
3	2020-21	1,654	982	948	474.00	276
4	2021-22	2,756	1,843	1,798	921.80	543
5	2022-23	3,124	2,216	2,178	1,128.60	714
	कुल	11,694	7,652	7,454	3,789.40	2,273

स्रोत: जिला उद्योग एवं व्यापार केंद्र (DIC), रीवा एवं MSME विभाग, म.प्र. शासन

विश्लेषण: सारणी 1 से स्पष्ट है कि वर्ष 2018-19 में जहाँ रीवा जिले में कुल 1,842 आवेदन प्राप्त हुए थे, वहीं 2022-23 में यह संख्या बढ़कर 3,124 हो गई, जो लगभग 69.6% की वृद्धि दर्शाती है। पाँच वर्षों में कुल 7,454 व्यक्तियों को लाभान्वित किया गया तथा ₹3,789.40 लाख का ऋण वितरित किया गया। वर्ष 2020-21 में कोविड-19 महामारी के कारण आवेदनों में अपेक्षाकृत कमी देखी गई। 2021-22 एवं 2022-23 में योजना की गति में उल्लेखनीय तेज़ी आई जो योजना के प्रति बढ़ती जागरूकता एवं प्रभावी क्रियान्वयन का संकेत है। पाँच वर्षों में 2,273 लाभार्थियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण भी प्रदान किया गया।

8.2 क्षेत्रवार लाभार्थी वर्गीकरण

सारणी 2:

मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना — क्षेत्रवार लाभार्थी वितरण एवं रोजगार सृजन

क्र.	उद्योग/सेवा क्षेत्र	लाभार्थी संख्या	प्रतिशत (%)	ऋण राशि (लाख रु.)	रोजगार सृजन
1	विनिर्माण उद्योग	1,842	24.71%	982.40	4,628
2	खाद्य प्रसंस्करण	1,248	16.74%	623.80	3,124

3	हस्तशिल्प एवं कुटीर उद्योग	1,124	15.07%	486.20	2,248
4	सेवा क्षेत्र	1,432	19.21%	724.60	3,580
5	व्यापार एवं वाणिज्य	986	13.23%	512.40	2,462
6	कृषि आधारित उद्योग	822	11.03%	460.00	2,056
	कुल योग	7,454	100%	3,789.40	18,098

स्रोत: जिला उद्योग एवं व्यापार केंद्र (DIC), रीवा — संकलित आंकड़े 2018-23

विश्लेषण: सारणी 2 के अनुसार विनिर्माण उद्योग सर्वाधिक 24.71% लाभार्थियों के साथ अग्रणी क्षेत्र है, जिसके पश्चात् सेवा क्षेत्र (19.21%) एवं खाद्य प्रसंस्करण (16.74%) का स्थान आता है। कुल मिलाकर इन तीन क्षेत्रों में लगभग 60.66% लाभार्थी केंद्रित हैं। रोजगार सृजन की दृष्टि से योजना ने कुल 18,098 प्रत्यक्ष रोजगार अवसर सृजित किए हैं। विनिर्माण क्षेत्र में 4,628 एवं सेवा क्षेत्र में 3,580 रोजगार के अवसर सर्वाधिक उल्लेखनीय हैं। कृषि आधारित उद्योगों में केवल 11.03% लाभार्थी हैं जो रीवा जैसे कृषि-प्रधान जिले में अपेक्षाकृत कम है — यह नीतिनिर्माताओं के लिए ध्यान देने योग्य पहलू है।

8.3 सामाजिक वर्गवार लाभार्थी वितरण

सारणी 3: मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना — सामाजिक वर्गवार लाभार्थी वितरण

क्र.	वर्ग	लाभार्थी संख्या	प्रतिशत (%)	महिला लाभार्थी	ऋण राशि (लाख रु.)
1	अनुसूचित जाति	1,862	24.98%	742	938.40
2	अनुसूचित जनजाति	1,486	19.94%	628	748.60
3	अन्य पिछड़ा वर्ग	2,218	29.76%	824	1,118.00
4	सामान्य वर्ग (BPL)	1,124	15.08%	412	566.80

5	अल्पसंख्यक वर्ग	764	10.25%	298	417.60
	कुल योग	7,454	100%	2,904	3,789.40

स्रोत: जिला उद्योग एवं व्यापार केंद्र (DIC), रीवा

विश्लेषण: सारणी 3 से ज्ञात होता है कि अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) सर्वाधिक 29.76% के साथ शीर्ष पर है, इसके पश्चात् अनुसूचित जाति (24.98%) एवं अनुसूचित जनजाति (19.94%) का स्थान है। यह आंकड़े योजना के सामाजिक समावेशन के लक्ष्य को दर्शाते हैं क्योंकि SC+ST+OBC मिलकर कुल लाभार्थियों का 74.68% भाग गठित करते हैं। महिला लाभार्थियों की संख्या कुल 2,904 (38.96%) है जो महिला सशक्तीकरण की दिशा में योजना के सकारात्मक प्रभाव को इंगित करती है, परंतु अभी भी 50% के लक्ष्य से पीछे है। अल्पसंख्यक वर्ग में केवल 10.25% लाभार्थी हैं जो उनकी योजना तक सीमित पहुँच को दर्शाता है।

8.4 ऋण वापसी एवं NPA की स्थिति

सारणी 4:

मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना — ऋण वापसी एवं NPA की स्थिति

क्र.	वर्ष	वितरित ऋण (लाख रु.)	वापसी राशि (लाख रु.)	वापसी प्रतिशत (%)	NPA प्रतिशत (%)
1	2018-19	548.60	412.40	75.18%	12.40%
2	2019-20	716.40	554.20	77.36%	11.82%
3	2020-21	474.00	328.60	69.32%	17.24%
4	2021-22	921.80	712.40	77.28%	10.86%
5	2022-23	1,128.60	896.40	79.43%	9.12%

स्रोत: राष्ट्रीयकृत बैंक रिपोर्ट, जिला लीड बैंक कार्यालय, रीवा

विश्लेषण: सारणी 4 के अनुसार वर्ष 2020-21 में कोविड-19 के प्रभाव से ऋण वापसी दर घटकर 69.32% हो गई तथा NPA 17.24% के उच्चतम स्तर पर पहुँच गया। परंतु 2021-22 एवं 2022-23 में क्रमशः सुधार होता गया और

2022-23 में ऋण वापसी दर 79.43% तथा NPA मात्र 9.12% रह गया। यह सुधार योजना में लाभार्थी चयन की बेहतर प्रक्रिया, प्रशिक्षण की गुणवत्ता में वृद्धि एवं प्रभावी अनुवर्ती (follow-up) कार्यवाही का परिणाम है। तथापि 9-12% के आसपास NPA स्तर अभी भी चिंताजनक है जो सुझाव देता है कि बाज़ार संपर्क एवं व्यावसायिक परामर्श को और सुदृढ़ किए जाने की आवश्यकता है।

8.5 विकासखंडवार लाभार्थी वितरण

सारणी 5:

मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना — रीवा जिले में विकासखंडवार लाभार्थी वितरण

क्र.	विकासखंड	आवेदन	स्वीकृत	लाभार्थी	ऋण (लाख रु.)
1	रीवा नगर	1,842	1,248	1,218	624.00
2	गुढ़	486	316	304	152.00
3	त्योंथर	542	348	334	167.40
4	सिरमौर	498	326	312	156.20
5	जवा	612	398	384	192.40
6	मउगंज	724	486	472	236.00
7	हनुमना	548	352	342	171.20
8	नईगढ़ी	486	312	298	149.00
9	रायपुर कर्चुलियान	468	296	284	142.60
10	चाकघाट	512	326	318	159.40
11	अन्य	2,976	1,844	1,788	835.20
	कुल	10,694	7,252	7,054	2,985.40

स्रोत: जिला उद्योग एवं व्यापार केंद्र (DIC), रीवा — 2018-23 (संकलित)

विश्लेषण: सारणी 5 से स्पष्ट होता है कि रीवा नगर क्षेत्र में सर्वाधिक 1,218 लाभार्थी हैं तथा वितरित ऋण भी सर्वाधिक ₹624.00 लाख है। इसके विपरीत गुढ़ एवं रायपुर कर्चुलियान जैसे दूरस्थ विकासखंडों में लाभार्थियों की संख्या अत्यंत सीमित है। यह भौगोलिक असंतुलन इंगित करता है कि योजना का लाभ शहरी एवं अर्ध-शहरी क्षेत्रों में अधिक केंद्रित है, जबकि दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में पहुँच अभी भी सीमित है। मउगंज विकासखंड में 472 लाभार्थियों के साथ अपेक्षाकृत अच्छा प्रदर्शन रहा है जो उस क्षेत्र में सक्रिय जन-जागरूकता अभियान का संकेत देता है।

9. निष्कर्ष (Conclusion)

प्रस्तुत शोध पत्र के विश्लेषण से निम्नलिखित प्रमुख निष्कर्ष उभरकर आते हैं:

प्रथम, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना रीवा जिले में औद्योगिक विकास एवं रोजगार सृजन की दिशा में एक प्रभावशाली नीतिगत हस्तक्षेप के रूप में उभरी है। पाँच वर्षों में 7,454 लाभार्थियों को ₹3,789.40 लाख का ऋण वितरण एवं 18,098 प्रत्यक्ष रोजगार अवसरों का सृजन इस योजना की ठोस उपलब्धि है।

द्वितीय, योजना सामाजिक समावेशन के अपने लक्ष्य को मोटे तौर पर पूरा कर रही है। SC, ST एवं OBC वर्ग के लाभार्थी कुल का 74.68% हैं। परंतु महिला लाभार्थियों का प्रतिशत (38.96%) लक्षित 50% से कम होना एक महत्त्वपूर्ण नीतिगत चुनौती है।

तृतीय, विकासखंडवार वितरण में स्पष्ट भौगोलिक असंतुलन है। शहरी एवं अर्ध-शहरी क्षेत्रों में योजना का लाभ अधिक केंद्रित है, जबकि दूरस्थ एवं वनाच्छादित विकासखंडों में पहुँच अत्यंत सीमित है।

चतुर्थ, कोविड-19 महामारी के बाद NPA में हुई वृद्धि के पश्चात् 2022-23 में NPA घटकर 9.12% पर आ जाना सकारात्मक है, परंतु ऋण वापसी की दर में और सुधार की संभावना विद्यमान है।

पंचम, कृषि आधारित उद्योगों में अपेक्षाकृत कम भागीदारी यह दर्शाती है कि रीवा जिले की कृषि-आधारित उद्यमिता क्षमता का समुचित दोहन अभी शेष है।

10. सुझाव (Suggestions)

उपरोक्त विश्लेषण एवं निष्कर्षों के आधार पर निम्नलिखित सुझाव प्रस्तुत किए जाते हैं:

1. दूरस्थ विकासखंडों तक पहुँच: गुढ़, सिरमौर, रायपुर कर्चुलियान एवं चाकघाट जैसे दूरस्थ विकासखंडों में विशेष शिविर एवं मोबाइल बैंकिंग सुविधा के माध्यम से योजना की पहुँच बढ़ाई जाए। प्रत्येक पंचायत स्तर पर योजना का प्रचार-प्रसार सुनिश्चित किया जाए।

2. महिला उद्यमिता को बढ़ावा: महिला लाभार्थियों हेतु विशेष ऋण सीमा, ब्याज सब्सिडी एवं स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से योजना का लाभ पहुँचाने की व्यवस्था की जाए। महिला उद्यमिता केंद्र स्थापित कर उन्हें विशेष परामर्श एवं मार्केटिंग सहायता प्रदान की जाए।

3. कृषि आधारित उद्योगों को प्रोत्साहन: रीवा जिले की कृषि विविधता का लाभ उठाते हुए मूल्य-वर्धन इकाइयाँ, खाद्य प्रसंस्करण, पुष्प उत्पादन, मशरूम उत्पादन एवं जैविक उत्पाद क्षेत्र में विशेष प्रोत्साहन पैकेज दिया जाए।

4. प्रशिक्षण की गुणवत्ता सुधार: प्रशिक्षण कार्यक्रमों को बाज़ार की आवश्यकताओं के अनुरूप अद्यतन किया जाए। उद्योग विशेषज्ञों, ।T। एवं पॉलिटेक्निक संस्थाओं को प्रशिक्षण प्रक्रिया में सम्मिलित किया जाए।

5. NPA में कमी: ऋण वितरण के पश्चात् छह माह तक नियमित अनुवर्ती (follow-up) की व्यवस्था की जाए। लाभार्थियों को लेखांकन, कर-प्रबंधन एवं उद्यम संचालन का बुनियादी प्रशिक्षण दिया जाए। बाज़ार संपर्क एवं ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से जोड़ने में सहायता प्रदान की जाए।

6. डिजिटलीकरण एवं पारदर्शिता: योजना की पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन किया जाए तथा लाभार्थियों को एसएमएस/WhatsApp के माध्यम से नियमित अपडेट भेजे जाएँ। शिकायत निवारण तंत्र को और अधिक प्रभावी एवं त्वरित बनाया जाए।

7. सौर ऊर्जा एवं हरित उद्योग: रीवा की सोलर सिटी पहचान का लाभ उठाते हुए सौर ऊर्जा उपकरण निर्माण, रखरखाव एवं संबंधित सेवाओं के क्षेत्र में विशेष उद्यमिता पैकेज तैयार किया जाए।

11. संदर्भ सूची (References)

1. शर्मा, राजेश (2018). मध्यप्रदेश में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का प्रभाव: एक समाजशास्त्रीय विश्लेषण. विकास अध्ययन पत्रिका, 12(3), 45-62.

2. मिश्रा, विनोद एवं पांडेय, सुरेश (2019). बघेलखंड में स्वरोजगार योजनाओं का तुलनात्मक अध्ययन. रीवा विश्वविद्यालय शोध पत्रिका, 8(2), 78-94.

3. यादव, कमला (2020). विंध्य क्षेत्र में सरकारी योजनाओं का औद्योगिक प्रभाव. अर्थशास्त्र एवं समाज, 15(1), 112-128.

4. NIESBUD (2021). Annual Report on Entrepreneurship Development in Central India. New Delhi: National Institute for Entrepreneurship and Small Business Development.

5. तिवारी, अशोक एवं सिंह, रामप्रसाद (2022). रीवा जिले की आर्थिक संरचना एवं उद्यमिता की संभावनाएँ. विंध्य शोध समीक्षा, 6(1), 22-38.

6. मध्यप्रदेश शासन (2023). मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना — वार्षिक प्रतिवेदन 2022-23. भोपाल: MSME विभाग, म.प्र. शासन.

7. जिला उद्योग एवं व्यापार केंद्र (2023). रीवा जिले में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की प्रगति रिपोर्ट. रीवा: DIC, म.प्र. शासन.

8. जिला सांख्यिकीय पत्रिका — रीवा (2022-23). रीवा: जिला योजना एवं सांख्यिकी कार्यालय.

9. भारत सरकार (2022). District Census Handbook — Rewa District. New Delhi: Office of the Registrar General & Census Commissioner.

10. राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण (NSS, 2022-23). रोजगार एवं बेरोजगारी सर्वेक्षण — मध्यप्रदेश. नई दिल्ली: MoSPI.

11. Gupta, Alok (2021). Micro-enterprise Development in Vindhya Region: Opportunities and Challenges. Indian Journal of Regional Economics, 4(2), 56-72.

12. सिंह, दिनेश एवं वर्मा, प्रीति (2022). मध्यप्रदेश में महिला उद्यमिता पर सरकारी योजनाओं का प्रभाव. समाजशास्त्र शोध पत्रिका, 9(4), 88-104.

13. World Bank (2020). Micro, Small and Medium Enterprise Finance in India. Washington D.C.: World Bank Group.

14. SIDBI (2022). Credit Flow to MSME Sector — Madhya Pradesh Report. Lucknow: Small Industries Development Bank of India.